



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3194]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2017/कार्तिक 29, 1939

No. 3194]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2017/KARTIKA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

का.आ. 3648(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) **वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम के रूप में वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)** (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसीआई) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से किया जाता है। यह स्कीम की दो भिन्न-भिन्न संघीय बजट 2003-04 और 2014-15 में घोषणा की गई थी;

और, स्कीम में उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने इस योजना के प्लान का क्रय किया है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) प्रतिफल की एक सुनिश्चित दर परिकल्पित है। स्कीम के अधीन निधियों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व उनके लिए आवंटित व्यय प्रबंध के उपबंध के साथ एलआईसीआई को सौंपा गया है और पॉलिसीधारकों को सुनिश्चित प्रतिफलों (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) में आयी ऐसी कमी, यदि कोई हो, जो स्कीम में परिकल्पित है, में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्—

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से, आधार संख्यांक होने का सबूत देने या अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) किसी व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने का इच्छुक हो और उसके पास आधार संख्यांक नहीं है या उसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, 31 दिसंबर, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्रास करने का भी हकदार हो तथा ऐसे व्यक्ति को आधार के लिए नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से, उसके कार्यान्वयन अभिकरण से, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, आधार नामांकन की सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा है तथा संबंधित ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में ऐसे आधार नामांकन केन्द्र के न होने की दशा में विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर नामांकन सुविधा प्रदान करेगा:

परन्तु जब तक व्यक्ति को आधार न दिया जाए तब तक ऐसे व्यक्तियों को, स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्वधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करवाया हो तो उसके आधार नामांकन पहचान (आईडी) पर्ची; अथवा

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट उसके आधार नामांकन संबंधी अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाक घर पासबुक; या (ii) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) राशनकार्ड; या (v) सरकारी कर्मचारी पहचान (आईडी) कार्ड; या (vi) मतदाता पहचान पत्र कार्ड; या (vii) मनरेगा कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (x) किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी तहसीलदार द्वारा उसके सरकारी लैटर हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति की फोटो वाला पहचान पत्र; या (xi) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उक्त दस्तावेज की जांच उस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा या उसके कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए विभाग उसके कार्यान्वयन अभिकरण तथा उसके अन्य कार्यालयों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा, अर्थात्:—

(1) स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा यदि उन्होंने पहिले से नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध समीपवर्ती आधार नामांकन केंद्रों में 31 दिसंबर, 2017 तक स्वयं को नामांकित करने का परामर्श दिया जाएगा तथा उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि उनके समीपवर्ती क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण स्कीम के अधीन फायदाग्राही नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राहियों से, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ (3) के पहले परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए

कार्यान्वयन अभिकरण के अभिहित पदधारियों के पास अथवा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. I-13016/01/2017-बीमा-I]

एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2017

S.O. 3648(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Financial Services (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Finance in the Government of India is administering the **Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY)** (hereinafter referred to as the Scheme) as a pension scheme for the senior citizens, implemented through Life Insurance Corporation of India (LIC) (hereinafter referred to as the Implementing Agency). The Scheme was announced in two versions in the Union Budgets 2003-04 and 2014-15;

And whereas, the Scheme envisages an assured rate of return to the individuals who purchase this plan (hereinafter referred to as the beneficiaries). LIC is entrusted with the responsibility of managing the funds under the Scheme with a provision of management expenses allocated there for, and the shortfall, if any, in the assured returns to the policy holders (hereinafter referred to as the benefit) as envisaged under the Scheme, which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar Enrolment by 31st December, 2017 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provision of section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or

Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

- (a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and
- (b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with Photo; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Voter Identity Card; or (vii) MGNREGS card; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on their official letter head; or (xi) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department or its Implementing Agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency and its other offices shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st December, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated official of the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. I-13016/01/2017-Ins.I]

N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor